

## संरक्षणवाद से संरक्षण

नीरज कुमार सिंह

यदि हम समय में वापस जाकर फ्रेडरिक बस्तियात से, 21वीं सदी के सन्दर्भ में, देशों के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पूछ सकते तो निःसंदेह उनकी सूची में संरक्षणवाद सबसे उपर होता। बस्तियात के लेखों को अगर वर्तमान के तराजू में तौला जाए तो यह बात न्ययसंगत ही जान पड़ती है कि आज वही देश समृद्ध हैं जहाँ संरक्षणवाद का काँटा समाज की नब्ज़ में सबसे कम गहराई तक धंसा है। बस्तियात उदारवाद के ऐसे व्याख्याता, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे जिन्होंने मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को इस सरलता से प्रस्तुत किया जिससे आम-आदमी भी तथाकथित गूढ़ आर्थिक नीतियों को समझ सके।

### धारा के विपरीत

फ्रांस में जन्मे बस्तियात ऐसे समय में उदारवाद के अधिवक्ता थे जब फ्रांस तेज़ी से समाजवाद की मरीचिका में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता खोज रहा था। ऐसे समय में बस्तियात ने संरक्षणवाद के अंतर्विरोधों से ना सिर्फ़ लोगों को अवगत कराकर विचारधाराओं को नयी दिशा दी बल्कि यह भी स्थापित किया कि प्रतिस्पर्धी बाज़ार सबके परस्पर हित में हैं। यही सिद्धांत दशकों बाद कल्याण अर्थशास्त्र के पहले प्रमेय का आधार भी बना। बस्तियात की दूरदर्शिता और बौद्धिक कौशल इस बात से भी प्रमाणित होती है कि उन्होंने मल्टिप्लाइयर सिद्धांत की झलक केन्स से दशकों पहले अपने लेख 'याचिका रोशनी करने वालों की' में दी थी। यही नहीं, टूटी हुई खिड़की के उदाहरण से उन्होंने केन्स के अर्थशास्त्र को प्रतिपादित होने से पहले ही खारिज कर दिया था। हायक का बस्तियात को 'प्रतिभा का प्रचारक' करार देना सटीक ही था।

### वर्तमान में प्रासंगिकता

'याचिका रोशनी करने वालों की' संरक्षणवाद पर बस्तियात का तीखा प्रहार है। इस लेख में बस्तियात ने अपनी विदग्ध लेखन-शैली से संरक्षणवाद के तर्कों का खोखलापन प्रत्यक्ष किया है। बस्तियात के दृष्टिकोण में मुक्त व्यापार का मतलब सिर्फ़ आयात कर का विरोध नहीं बल्कि न्याय, चयन की स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार का

सवाल भी था। बस्तियात का मूल प्रबंध यह है कि संरक्षणवाद पक्षपातपूर्ण नीतियों से प्रतिस्पर्धा के प्राकृतिक समन्वय को बिगड़ता है।

आज डेढ़ सौ साल बाद भी संरक्षणवाद समाज में उपस्थित है। उसका मूल बस्तियात के समय जैसा ही है: उत्पादकों के हितों का संरक्षा और उपभोक्ताओं की उपहासना। 'याचिका' द्वारा बस्तियात दो मूलभूत सिद्धांत देते हैं। पहला, संरक्षणवाद के विशेष विरोध में और दूसरा सामान्य तौर पर सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध। इन दोनों ही सिद्धांतों की समसामयिक प्रासंगिकता दो उदाहरणों से सिद्ध होती है।

## १. उद्योग संरक्षणवाद

संरक्षणवाद से जन्मी आयात प्रतिस्थापन नीति दशकों तक भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी अवरोधक रही। इस नीति की खामियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है की पूर्व एशिया के कई देश, जो 1950 में भारत से आर्थिक रूप पीछे थे, अपेक्षाकृत मुक्त व्यापार की नीतियों के बलबूते पर 1990 तक भारत से कहीं आगे निकल गये। यही नहीं, आयात प्रतिस्थापन को अपनाने वाले लगभग सारे देश अभी तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। संरक्षणवाद की चर्चा करते हुए बस्तियात ने 1845 में ही हमें परोक्ष रूप में आयात प्रतिस्थापन जैसी नीतियों के दोषों से अवगत करा दिया था।

## २. श्रम कानून

भारत में करीब 92 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं, जहाँ न तो उन्हें न्यायपूर्ण वेतन मिलता है, और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा। इस खेदजनक स्थिति के ज़िम्मेदार, अप्रत्याशित रूप से, वही सरकारी नियम हैं जो सतही तौर पर तो श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन असल में उनकी स्थिति बद से बदतर बनाते हैं। चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अधिनियम, 1948 हो या कांट्रैक्ट लेबर अधिनियम, 1970, सरकार ने श्रमिकों के संरक्षण के लिए उद्योगों पर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं। इसका सीधा परिणाम यह है कि उद्योग कम-से-कम श्रमिकों को काम पर रखना चाहते हैं और नतीज़तन, अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने को विवश हैं। श्रमिकों के संरक्षण के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करते वक़्त सरकार शायद यह भूल गयी कि श्रमिकों का हित वहीं है जहाँ बाज़ार का हित है।

## सरकार की भूमिका

बस्तियात ने 'द लॉ' में सुस्पष्ट किया है की राजनीतिक हस्तक्षेप का मूलभूत उद्देश्य लूट है। प्रतिस्पर्धी बाज़ार चयन और स्वतंत्रता द्वारा स्वयं ही उत्पादक और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं। 'याचिका' में बस्तियात ने उद्धृत किया है कि ऐसे बाज़ार में सरकारी हस्तक्षेप अकल्याणकारी होता है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी मूलभूत सुविधाएँ, संपत्ति अधिकार और कानून उपलब्ध कराए जिससे उपभोक्ता और उत्पादक बिना किसी अवरोध के व्यापार कर सकें। सरकारी हस्तक्षेप सिर्फ़ वहीं मान्य है जहाँ बाज़ार असफल सिद्ध होते हैं।

हॉब्स ने सरकार को लेवाइयतन (दानव) कहा था। यह सरकार को निर्धारित करना है की वह हस्तक्षेप करके अकल्याणकारी दानव बनना चाहती है या अहस्तक्षेप से कल्याणकारी सुकारक। लेकिन सरकार को बस्तियात के लेखों से उद्धृत यह सिद्धांत समझना आवश्यक है की न्यूनतम शासन ही श्रेष्ठ शासन है।

(शब्द संख्या: 768)

## सन्दर्भ

1. फ्रेडरिक बस्तियात, याचिका रोशनी करने वालों की, 1845. [www.azadi.me](http://www.azadi.me) पर उपलब्ध
2. फ्रेडरिक बस्तियात, क्या देखा जाता है और क्या नहीं देखा जाता है, 1850. [www.azadi.me](http://www.azadi.me) पर उपलब्ध
3. फ्रेडरिक बस्तियात, द लॉ, 1850. [www.azadi.me](http://www.azadi.me) पर उपलब्ध
4. फ्रेडरिक बस्तियात का जीवन परिचय, [www.azadi.me](http://www.azadi.me) पर उपलब्ध
5. [www.bastiat.org](http://www.bastiat.org)